भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2198
मंगलवार, 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

†2198. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में अपने महाविद्यालयों में सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देने वाला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में सहकारिता क्षेत्र में कारोबार के विस्तार के लिए सरकार शीघ्र कोई नई सहकारिता की नीति भी लाने वाली है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । देश में सहकारी आंदोलन की बुनियाद सशक्त करने के लिए सहकारी विश्वविद्यालय को स्थापित करने की आवश्यकता है । इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ।

यह मंत्रालय एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण की प्रक्रिया में है । नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण के लिए दिनांक 2 सितम्बर, 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) एवं सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है । नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण से 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना साकार होगी, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, देश में सहकारी आंदोलन सशक्त होगा और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक होगी । इस संदर्भ में हितधारकों के साथ पूर्व में परामर्श किए गए थे और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारी संगठनों, संस्थानों तथा आम जनता से भी सुझाव मांगे गए थे । नई नीति का प्रारूप बनाने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की समिति समेकित फीडबैक, नीति सुझावों और सिफारिशों का विश्लेषण करेगी ।

*****